O.P. JINDAL GLOBAL
INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE
UNIVERSITY
A Private University Promoting Public Service

JINDAL INSTITUTE OF HARYANA STUDIES

सोनीपत

मानव विकास रिपोर्ट

कार्यकारी सारांश

2026

कार्यकारी सारांश

संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर/HDR) में 193 देशों में से भारत को 130वें स्थान पर रखा गया है। पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार देखा गया है, लेकिन भारत अब भी मानव विकास की मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। वर्ष 2017-18 में भारत के 14 राज्य उच्च मानव विकास की श्रेणी में थे, जिसमें हरियाणा एक था। विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में एचडीआर (HDR) के योगदान को व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार की वैश्विक-स्तरीय रिपोर्ट (जो विभिन्न देशों की प्रगति पर नज़र रखती है) और राष्ट्रीय-स्तरीय रिपोर्ट (जो देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों की प्रगति पर नज़र रखती है) का लगातार प्रकाशन किया जाना इस बात का प्रमाण है। हालांकि भारत में उप-राज्य स्तरीय एचडीआर का प्रकाशन भी किया गया है, लेकिन यह आठ राज्यों के कुछ ही जिलों तक ही सीमित है। सोनीपत जिले की इस एचडीआर (HDR) के प्रकाशन के बाद, उन राज्यों की संख्या में अब एक और राज्य जुड़ जाएगा, जिनके कम से कम एक जिले की एचडीआर (HDR) प्रकाशित की गई है।

सोनीपत हरियाणा के 22 जिलों में से एक है, जो राज्य के पश्चिमी इलाके में स्थित है, और इसकी सीमा देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। सोनीपत जिला ऐतिहासिक महत्व रखता है और अब इसे उपनगरीय इलाके की श्रेणी में रखा जाता है, जो फिलहाल कृषि, पर्यावरण और स्थानिक स्तर पर कई गहरे बदलावों से गुज़र रहा है। सोनीपत की यह मानव विकास रिपोर्ट न सिर्फ जिले में विकास मानकों की मौजूदा स्थिति पर रोशनी डालती है, बल्कि भविष्य को आकार दे रही प्रक्रियाओं, असमानताओं और चुने गए नीति विकल्पों की पड़ताल भी करती है। इस रिपोर्ट में संदर्भ के अनुसार, इन सात विषयों से जुड़े श्रेणीवार आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है - शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, स्थानिक परिवर्तन, बुनियादी सेवाएं और पर्यावरण - ताकि जिले के बदलते परिवेश और उभरती चुनौतियों के विश्लेषण के ज़रिए जिले के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इन सभी विषयों पर सोनीपत जिले की मौजूदा स्थिति के आंकलन के लिए हमने स्थानीय ज्ञान, सामाजिक-आर्थिक जानकारी, प्रशासनीय दस्तावेज़, और उपलब्ध गैर-प्राथमिक आंकड़ों की मदद ली है। विभिन्न जिलों के बीच तुलना कर पाने के लिए ज़रूरी आंकड़ों की कमी के चलते, इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई/HDI) का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं की गई है। सीमित और पुराने हो चुके जिले-वार आंकड़ों के आधार पर एचडीआई (HDI) का तुलनात्मक विश्लेषण गलत निष्कर्षों की ओर ले जा सकता है। इस रिपोर्ट में सोनीपत जिले की आतंरिक विकास प्रक्रिया पर ज़ोर दिया गया है और पिछले दशकों में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए, विभिन्न समुदायों के विकास की बारीकियों और उनमें मौजूद रुकावटों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

शासन

विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को जन-जीवन की वास्तविकताओं में बदलने के लिए शासन बहुत महत्व रखता है। सोनीपत जिले में व्यापक सड़क नेटवर्क से लेकर ई-शासन तक, बुनियादी ढांचा बहुत मज़बूत है। लेकिन, इन पर कानून व्यवस्था से जुड़ी निरंतर चुनौतियाँ, अदालतों में होने वाली देरी, जन भागीदारी की कमी, और भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं जैसी समस्याएं हावी हो जाती हैं।

जिले के प्रशासनिक और सांस्थानिक ढांचे के अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट शांति, न्याय और मज़बूत संस्थानों पर टिकी नीतियों की सिफारिश करना चाहेगी। इस दिशा में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-

- विकेन्द्रीकृत शासन को और गहरा बनाने के लिए जन सहभागिता के साथ योजना बनाने, बजट तैयार करने और उस पर निगरानी (मॉनिटरिंग) रखने से जुड़ी **ब्लॉक- और पंचायत-स्तरीय क्षमताओं** का विकास किया जाए।
- लंबित मामलों की संख्या घटाने, अपराध कम करने और कमज़ोर समुदायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए **कानूनी साक्षरता,** न्याय तक पहुँच, और वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए।
- स्थानीय शासन प्रणालियों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों और युवाओं के **समावेशी प्रतिनिधित्व और नेतृत्व** को बढ़ावा दिया जाए।
- पारदर्शिता, लाभार्थियों के साथ सीधे संपर्क, शिकायतों के निवारण, और सेवाओं की रियल-टाइम निगरानी के लिए **प्रौद्योगिकी** की सहायता ली जाए।
- विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज के साथ मिलकर मानव विकास में हो रही प्रगति पर नज़र रखने (मॉनिटरिंग), जन संवाद आयोजित करने और विकास प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला "निगरानी केंद्र" स्थापित जाए।

स्वास्थ्य

एक स्वस्थ आबादी ही खुशहाली और आर्थिक उत्पादकता की बुनियाद होती है। सोनीपत कई पैमानों पर हरियाणा राज्य के कई अन्य जिलों से और राज्य और राष्ट्रीय औसत से आगे है। सोनीपत के स्वास्थ्य संकेतकों का विश्लेषण दर्शाता है कि जिले में स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली डिलीवरी (प्रसव) के अनुपात में और अनुमानित जीवन-अवधि में काफी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर भी अब अपने सतत विकास लक्ष्य के नज़दीक पहुँच चुकी है। लेकिन, बाल और मातृ स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संक्रामक रोगों के स्तर में अब भी कई कमियां मौजूद हैं, जो सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी, जलवायु-संबंधित कमज़ोरियों और एक बड़ी प्रवासी आबादी के कारण और ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती हैं।

सोनीपत एचडीआर के लिए किए गए विश्लेषण के आधार पर जिले की आबादी के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव और सिफारिशें इस प्रकार हैं-

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की समान पहुँच को प्राथमिकता देते हुए, मौजूदा 164 उपकेंद्रों के अलावा **200 नए उपकेंद्र** शुरू किए जाएं, मौजूदा 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा **30 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र** शुरू किए जाएं, 7 मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा **9 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र** खोले जाएं ताकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को पूरा किया जा सके और इलाज पर जेब से होने वाले खर्च को घटाया जा सके।
- इसके साथ-साथ, इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में **कर्मचारियों के सभी पदों** को स्थायी रूप से भरा जाए।
- सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को **न्यूनतम वेतन** दिया जाए।
- **पोर्टेबल सुविधाओं (जो किसी एक स्थान से बंधी न हों) और मोबाइल स्वास्थ्य केंद्रों** के ज़रिए प्रवासियों, कम वेतन वाले श्रमिकों, और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाया जाए।

शिक्षा

शिक्षा के मामले में सोनीपत जिले के पिछले कुछ दशकों के सफर में, जिले में मौजूद शैक्षणिक संस्थानों की बड़ी संख्या भी झलकती है और लम्बे समय से चली आ रही गैर-बराबरी भी, जो मानव संसाधन विकास में रुकावट बन गई है। शिक्षा तक पहुँच में बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है- युवाओं में साक्षरता दर और प्राथमिक शिक्षा में भर्ती दर अब लगभग 100 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। लड़कियों, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं ने समावेश को बढ़ावा दिया है और इन समुदायों के छात्रों को स्कूल में रखने में मदद की है। लेकिन, शिक्षा की गुणवत्ता, हाशिए के और ग्रामीण समुदायों के छात्रों में स्कूल छोड़ कर जाने की दर, लिंग-आधारित असमानताएं और डिजिटल गैर-बराबरी आज भी गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। सोनीपत में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों में, पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में मिश्रित रुझान दिखाई देते हैं - उच्च शिक्षा कर्मचारियों में जहाँ यह अनुपात काफी संतुलित है, वहीं गैर-शिक्षण कर्मचारियों में पुरुषों का दबदबा बना हुआ है, जो पेशों में मौजूद लिंग-आधारित विभाजन के आज भी मज़बूत होने की ओर इशारा करता है।

बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, सोनीपत में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

- **औद्योगिक गलियारों को डिजिटल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों** से जोड़ा जाए ताकि महिलाओं और युवाओं को रोज़गार के लिए तैयार किया जा सके। जापान-इंडिया इंस्टिट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग (जेआईएम/JIM) सोनीपत, फिलहाल कारखानों के काम से जुड़े कौशल पर प्रशिक्षण देता है, लेकिन ये महिलाओं और ग्रामीण युवाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसमें सुधर किया जाना चाहिए।
- आईटीआई केंद्रों का विस्तार: **दिव्यांग व्यक्तियों** के लिए विशेष आईटीआई खोले जाएं।
- **आईटीआई केंद्रों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए।** हरियाणा में करीब 55 प्रतिशत आईटीआई केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। सोनीपत में करीब 70 प्रतिशत आईटीआई केंद्र सरकारी हैं, और सिर्फ 30 प्रतिशत ही निजी इकाइयों द्वारा संचालित हैं, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत सीमित है।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार:** सोनीपत में फिलहाल सिर्फ छह व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जबकि हरियाणा में हर जिले में ऐसे औसतन दस संस्थान हैं। इन संस्थानों के विस्तार से युवाओं में कौशल का विकास होगा और रोज़गार पाने की उनकी क्षमता का भी।

- शिक्षण कर्मचारियों में **अनुसूचित जातियों** की भागीदारी को मौजूदा 3.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत तक लाया जाए, जो उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के छात्रों के अनुपात के बराबर होगा।

आजीविका

भारत को अगर एक युवा देश होने का लाभ उठाना है, तो गरिमापूर्ण, उत्पादक रोज़गार सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। सोनीपत में रोज़गार में हुए व्यवस्थागत बदलाव के तहत श्रमिक कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादकता वाले औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की ओर गए हैं। लेकिन अनिश्चित, अनौपचारिक रोज़गार, वेतन दर में बढ़ोत्तरी की कमी और लिंग-संबंधी रुकावटों की समस्या आज भी कायम है। श्रमिकों में महिलाओं की बढ़ती हुई तादाद, विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र में, एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन वेतन में बढ़ोत्तरी और अच्छी नौकरियों की संख्या अब भी काफी पीछे हैं। रोज़गार में हुए व्यवस्थागत परिवर्तन के बावजूद, सोनीपत में आमदनी में हुई बढ़ोत्तरी, देश के औसत से कम है, जो खुशहाली के नज़रिए से अच्छा नहीं है। हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि इसके पीछे पिछले छह सालों में सेवा क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की आमदनी में आई गिरावट है।

जिले में हो रहे व्यवस्थागत परिवर्तन का लाभ सभी श्रमिकों तक पहुँचाने के लिए हमारे अध्ययन से निम्न सिफारिशें निकल कर आती हैं-

- रोज़गार और आजीविका से जुड़ी योजनओं की रूपरेखा तय करते समय कौशल की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर, औद्योगिक गलियारों से जुड़े आर्थिक इलाकों, और ग्रामीण इलाकों के गैर-कृषि क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए।
- **कौशल विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, और उनके कार्यान्वयन पर नज़र रखी जाए, और इनके तहत विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा युवाओं पर ज़ोर दिया जाए** ताकि उन्हें अर्थपूर्ण कौशल हासिल हों और वे बढ़ते रोज़गार बाज़ार में बेहतर तरीके से भाग ले पाएं।
- सामाजिक सुरक्षा, पंजीकरण और राज्य तथा केंद्रीय सरकार की योजनाओं में शामिल किए जाने के ज़रिए अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण दिया जाए।
- छोटी जोत के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय समावेश, उद्योग प्रशिक्षण, और पूंजी तक उनकी पहुँच को प्राथमिकता दी जाए, और इसके लिए भूमिहीनता, डिजिटल साक्षरता, और बाजार तक पहुँच जैसी रुकावटों को दूर किया जाए।
- ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में गैर-कृषि रोज़गार और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए - कृषि क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और डिजिटल रोज़गारों को एक दूसरे से जोड़ा जाए।

स्थानिक परिवर्तन

सोनीपत में पिछले कुछ दशकों में अप्रत्याशित स्थानिक परिवर्तन देखा गया है, जिसमें तेज़ी से हुआ औद्योगिक और शैक्षणिक विस्तार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाना, और बड़ी परियोजनाओं की वजह से बुनियादी ढांचे में हुए सुधार शामिल हैं। विविध प्रकार के शहरी केंद्र, घने औद्योगिक इलाके, प्रमुख शैक्षणिक केंद्र, और नए आर्थिक गलियारे भी इस स्थानिक परिवर्तन के कारण रहे हैं। सोनीपत की इन विशेषताओं ने पूँजी को आकर्षित किया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिले को देश और विदेश से जोड़ा है, जिसकी वजह से सोनीपत इस क्षेत्र के आर्थिक केंद्रबिंदु के रूप में उभरा है। लेकिन शासन के स्तर पर समन्वय के अभाव में और बाज़ारों में हो रही सट्टेबाज़ी के कारण, विकास प्रक्रिया में असंतुलन और गहरी होती हुई सामाजिक-स्थानिक असमानताएं देखी जा सकती हैं, विशेष रूप से कम-आमदनी और प्रवासी आबादी में।

जिले में समतामूलक और योजनाबद्ध परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

- अगले दो सालों में एचएसवीपी (HSVP), एचएसआइआइडीसी (HSIIDC) और नगर-पालिकाओं की योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **जिला स्थानिक समन्वय समिति** का गठन किया जाए। इस समिति द्वारा एक एकीकृत जिला स्थानिक रूपरेखा (2025-2035) तैयार की जाए जो परिवहन, औद्योगिक, और आवासीय ज़ोनिंग को रोज़गार और पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़े।
- **पारदर्शी लाइसेंसिंग, सट्टेबाज़ी के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली संपत्ति की ऊपरी सीमा निर्धारित करने और समावेशी ज़ोनिंग प्रक्रिया** के माध्यम से भूमि और आवासीय बाज़ारों को नियंत्रित किया जाए ताकि किफायती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- पूरे जिले में महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाए जो उन्हें आने-जाने की आज़ादी देगा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

बुनियादी सेवाएं

सोनीपत जिले में बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में कई उपलब्धियां देखी जा सकती हैं, जिसमें साफ़ पानी की व्यापक उपलब्धता, जिसके तहत लगभग सभी घरों को बोरवेल या पाइप के ज़रिए जल सेवा दी जा रही है; शहरी और ग्रामीण इलाकों में घर-घर से सूखा कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्थित कचरा प्रबंधन सेवा; और घरेलू तथा कृषि-संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने वाला लगातार फैलता हुए बिजली संपर्क नेटवर्क शामिल हैं। जिले में कई सीवेज (मलजल) उपचार संयंत्र लगाए गए हैं और सीवरेज नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है, खासतौर पर शहरी इलाकों में। कचरे से ऊर्जा बनाने वाला एक संयंत्र भी लगाया गया है और कचरे की रीसाइक्लिंग के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो शहरी प्रशासनीय संस्थानों द्वारा प्रभावी प्रबंधन का संकेत देता है। तेज़ी से हुए शहरी विकास के बावजूद, जिले के मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाएं की मदद से जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है, हालांकि ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में स्वछता से जुड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।

रिपोर्ट के लिए किए गए विश्लेषण के आधार पर बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं-

- सीवरेज नेटवर्क और सीवेज उपचार क्षमता के विस्तार और आधुनिकरण को और तेज़ किया जाए, और उपनगरीय तथा ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों को कम किया जा सके।
- कम से कम दो औद्योगिक क्षेत्रों (राय, खरखौदा) की भूमिगत नाली व्यवस्था को नज़दीक के गांवों तक बढ़ाया जाए ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य खतरों को कम किया जा सके।
- भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू किया जाए, सतही जल आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाए, और निजी बोरवेल के ज़रिए भूजल के उपयोग को नियंत्रित किया जाए।
- आवास निर्माण को बुनियादी सेवा प्रबंधन से जोड़ने वाली समन्वित योजना प्रक्रिया के ज़रिए किफायती आवासीय सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाई जाए, विशेष रूप से कम आमदनी वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए। किफायती मकानों में से कम से कम 20 प्रतिशत का निर्माण एचएसआइआइडीसी (HSIIDC) औद्योगिक केंद्रों के आसपास के इलाकों में किया जाए।
- बाढ़ प्रबंधन और नालियों के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण को रोका जाए, नालियों से गाद निकालने का काम नियमित रूप से किया जाए, बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाए, और आपदाओं से निपटने की तैयारी बढ़ाई जाए।

पर्यावरण

पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में मानवीय अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे बन गए हैं, और ये सोनीपत के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां, खासतौर पर सोनीपत जिले में, भूमि की बदहाली, भूजल के पतन, वायु और जल प्रदूषण, और साझा संसाधनों की क्षति के चलते और गहरी होती जा रही हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य हाशिए के समुदायों की खुशहाली और आर्थिक सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है।

हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (एचसीएपीएसडी/ HCAPSD), राज्य पर्यावरण परियोजना (एसईपी/SEP), अमृत (AMRUT) और जल जीवन मिशन जैसी मौजूदा सरकारी योजनाएं प्रदूषण नियंत्रण, पराली प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषित जल के उपचार को मज़बूत बनाती हैं। जल संरक्षण और समतामूलक भूमि सुधार के साथ-साथ इन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, आजीविका को बेहतर बनाएगा, और जिले को सतत विकास की ओर ले कर जाएगा।

हमारे विश्लेषण से उभर कर आने वाली कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

- **टिकाऊ कृषि पद्धतियां** (कम पराली वाली, कम सिंचाई वाली, जैविक और विविधतापूर्ण फसलें) अपनाने और मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाए, विशेष रूप से छोटी जोत के किसानों और महिला किसानों को।
- **महिलाओं के नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ/FPO) को बढ़ावा** दिया जाए। जून 2025 तक, हरियाणा में 179 एफपीओ (FPO) की स्थापना हुई है, जो कई अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इनमें से भी मुट्ठी भर ही महिलाओं के नेतृत्व में हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ (FPO) को समर्थन दिया जाए, जो बाज़ार तक उनकी पहुँच और बैंक जैसी संस्थाओं से क़र्ज़ ले पाने की उनकी क्षमता बढ़ाएगा और उन्हें आमदनी अर्जित करने के विविध विकल्प उपलब्ध कराएगा।
- सोनीपत के उपनगरीय कृषि इलाकों में **सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों** और जलवायु-उपयुक्त भूमि और जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल, सोनीपत में ज़्यादातर

सिंचाई नहरों (55.9 प्रतिशत) और बोरवेल (44.1 प्रतिशत) के माध्यम से की जाती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें **सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले जल की मात्रा को 40-60 प्रतिशत तक घटा सकती हैं और पैदावार को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं।**

- जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित होने वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए (**न्यूनतम समर्थन मूल्य, वापस खरीद की व्यवस्था** के ज़रिए) - दलहन और सब्ज़ियों जैसी फसलें गेंहूं-धान की एक-फसल खेती के मुकाबले 13 प्रतिशत (राष्ट्रीय स्तर पर) ज़्यादा मुनाफा देती हैं।
- **समुदाय में जागरूकता और स्कूल में पर्यावरण शिक्षा** का विस्तार किया जाए ताकि जिले भर में नागरिकों को जलवायु संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सोनीपत अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। आंकड़ों की कमी की वजह से, विशेष रूप से जिले के स्तर पर, अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार, स्थानीय जलवायु में हो रहे बदलाव और कमज़ोर समुदायों की ज़रूरतों को समझना मुश्किल है। लेकिन शासन प्रक्रियाओं में जन-भागीदारी, स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अब भी चुनौती बने हुए हैं। भूमि, रोज़गार, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लिंग-आधारित असमानताएं आज भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की ज़रुरत है। जलवायु अस्थिरता और शहरी विस्तार के चलते, मौजूदा चुनौतियां और भी जटिल हो गई हैं जो नई प्रकार की लचीली लोक नीतियों और लोक भागीदारी की मांग करती हैं। बहुआयामी सूचकांकों पर आधारित विश्लेषण की मदद से, व्यवस्थागत बाधाओं और रचनात्मक समाधानों को प्रस्तुत कर, विभिन्न समूहों और क्षेत्रों के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाने के उद्देश्य के साथ, सोनीपत की यह मानव विकास रिपोर्ट अल्पकालिक बदलाव के साथ-साथ दीर्घकालीन परिवर्तन की दिशा दिखा पाने का एक प्रयास है।

क्षेत्रीय योजनाओं को एक-दूसरे से जोड़ने पर - जैसे शिक्षा को आजीविका से, जलवायु संरक्षण को स्वास्थ्य से, और शासन को सामाजिक समावेश से जोड़ने पर- ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि एकीकृत योजनाओं को बढ़ावा मिले और सरकारी खर्च से प्रभावी परिणाम हासिल हों। महिला सशक्तिकरण, भूमि अधिकार, रचनात्मक आवास योजनाएं, पर्यावरण प्रबंधन, और रणनीतिक स्थानिक सुधारों के माध्यम से जिले में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। यही नहीं, नीतियों को ज़मीनी-स्तरीय परिवर्तन में बदलने के लिए, इनके कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी (मॉनिटरिंग), समय-समय पर इनकी समीक्षा और बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजना में ज़रूरी बदलाव कर पाने की क्षमता की ज़रुरत होगी। इसलिए, सोनीपत मानव विकास रिपोर्ट की इस पहल को हम सिर्फ एक बार की जाने वाली समीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली एक मुहिम के रूप में देखते हैं, जो जिले की प्रगति पर नज़र रखने, प्राथमिकताओं में फेरबदल करने और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को स्थानीय विकास के केंद्र में रखने में सरकार, नागरिक समाज, शोधकर्ताओं और नागरिकों की सहायत करेगी। हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सामूहिक कार्यवाही की लौ जलाने वाली चिंगारी साबित होगी। नीति-निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, शोधकर्ता, शिक्षाविद, और सोनीपत के सभी समुदाय बदलाव के गवाह भी हैं और उनके वाहक भी। यह सोनीपत मानव विकास रिपोर्ट जिले के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है - एक ऐसा जिला जो अपनी विशेषताओं और अपनी चुनौतियों, दोनों के प्रति जागरूक है, और जो सभी लिंग, जाति और पृष्ठभूमियों से आने वाले निवासियों को लम्बा, स्वस्थ और भरपूर जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

O.P. JINDAL GLOBAL
INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE
UNIVERSITY
A Private University Promoting Public Service

JINDAL INSTITUTE OF HARYANA STUDIES

O. P. Jindal Global University Sonipat Narela Road, Near Jagdishpur Village, Sonipat – 131001, Haryana, India

JGU- An Initiative of Jindal Foundation

www.jgu.edu.in

jindalglobaluni jindalglobaluni jindalglobaluni jindalglobaluni jguvideo